भारत - सिंगापुर संबंध

पृष्ठभूमि

भारत और सिंगापुर के बीच घनिष्ठ संबंधों का एक इतिहास है जो मजबूत वाणिज्यिक, सांस्कृतिक एवं जन दर जन संपर्कों पर आधारित है। सिंगापुर के साथ भारत के संबंध चोल वंश के समय से चले आ रहे हैं। अधिक आधुनिक संबंध का श्रेय सर स्टाम्फोर्ड रैफल्स को जाता है जिन्होंने 1819 में सिंगापुर में मलक्का जलडमरूमध्य पर एक व्यापार केन्द्र का निर्माण किया था जो ब्रिटिश भारत के तहत उपनिवेश बन गया तथा कलकत्ता से अभिशासित हुआ (1830-1867)। औपनिवेशिक संबंध संस्थाओं एवं प्रथाओं की समानता, अंग्रेजी के प्रयोग तथा भारी संख्या में भारतीय समुदाय की मौजूदगी में परिलक्षित होता है।

1965 में सिंगापुर की आजादी के बाद संबंध विशेष रूप से घनिष्ठ हुए क्योंकि पहले प्रधानमंत्री ली कुआन यू ने राष्ट्र निर्माण, क्षेत्रीय सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय मान्यता के अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में भारत से मदद की उम्मीद की। 1990 के दशक में भारत के आर्थिक सुधारों तथा भारत की पूरब की ओर देखो नीति ने सहयोग की एक नई रूपरेखा का सृजन करने का अवसर प्रदान किया।

सामरिक साझेदारी

प्रधानमंत्री मोदी की सिंगापुर यात्रा के दौरान इस मजबूत संबंध को सामरिक साझेदारी के रूप में स्तरोन्नत किया गया, जिन्होंने राजनयिक संबंधों की स्थापना की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर 23 और 24 नवंबर 2015 को सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली हुसैन लूंग के साथ सामरिक साझेदारी के लिए एक संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किए।

नवंबर 2015 में प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा के दौरान रक्षा, समुद्री सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, स्वापक पदार्थों का दुर्व्यापार, शहरी आयोजना, नागर विमानन तथा संस्कृति के क्षेत्रों में 9 द्विपक्षीय दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए गए / आदान प्रदान किया गया तथा एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया गया जिसने सहयोग एवं आपसी हित के क्षेत्रों को रेखांकित किया। राजनयिक संबंधों की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर दोनों प्रधानमंत्रियों द्वारा दोनों देशों के राष्ट्रपति भवनों को दर्शाने वाली संयुक्त संस्मारक डाक टिकटें जारी की गईं। प्रधानमंत्री मोदी ने नेताजी स्मारक में श्रद्धांजलि अर्पित की, 'भारत की सिंगापुर गाथा' नामक 37वां सिंगापुर व्याख्यान दिया, तकनीकी सहयोग संस्थान (आ ई टी ई) का दौरा किया और भारत ' सिंगापुर आर्थिक सम्मेलन में कारोबारी समुदाय को तथा सिंगापुर में भारतीय समुदाय को संबोधित किया जहां 20000 के आसपास लोग एकत्र हुए थे।

यात्राओं का आदान - प्रदान

प्रधानमंत्री मोदी ने इससे पहले 2015 में 29 मार्च को ली कुआन यू के राजकीय अंतिम संस्कार में भाग लेने के लिए सिंगापुर का दौरा किया था। हमारे ध्वजों को आधा झुकाने के साथ भारत में शोक दिवस के रूप में अंतिम संस्कार दिवस की घोषणा के साथ अंतिम संस्कार में प्रधानमंत्री की भागीदारी की सिंगापुर सरकार द्वारा दिल से प्रशंसा की गई।

सिंगापुर के राष्ट्रपति टोनी तान केंग याम ने राजनयिक संबंधों की स्थापना की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर 8 से 11 फरवरी 2015 के दौरान भारत का राजकीय दौरा किया था। उनकी इस यात्रा के दौरान भारत में सिंगापुर द्वारा संस्मारक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया जिसमें राष्ट्रीय संग्रहालय में पेरनाकन प्रदर्शनी, सिंगापुर खाद्य महोत्सव तथा सिंगापुर - भारत विपक्षी संबंधों पर एक पुस्तक का विमोचन शामिल है। अगस्त 2014 से सिंगापुर में भारत द्वारा आयोजित अनेक संस्मारक कार्यक्रमों की भरपूर सराहना की गई तथा इनमें पोतों की यात्राएं, सांस्कृतिक कार्यक्रम, एशियाई सभ्यता संग्रहालय में "भारतीय संग्रहालय, कोलकाता से एशिया के सबसे पुराने संग्रहालय से बौद्ध कला रूपों के धरोहर" नामक बौद्ध कला प्रदर्शनी, फिल्म महोत्सव, खाद्य महोत्सव आदि शामिल थे।

दोनों पक्षों से यात्राओं के एक सक्रिय कलेंडर ने द्विपक्षीय संबंधों की गति और बढ़ा दी है। भारत की ओर से अनेक यात्राएं हुई हैं जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं : मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री की जनवरी 2016 में सिंगापुर यात्रा; विश्व बैंक तथा सिंगापुर सरकार द्वारा आयोजित अवसंरचना वित्त शिखर बैठक 2015 में मुख्य वक्ता के रूप में भाग लेने के लिए 20 और 21 अक्टूबर 2015 को रेल मंत्री श्री सुरेश प्रभु की सिंगापुर यात्रा; 18 और 19 सितंबर 2015 को वित्त मंत्री तथा कारपोरेट कार्य एवं सूचना और प्रसारण मंत्री श्री अरुण जेटली की सिंगापुर यात्रा; सिंगापुर की स्वतंत्रता के 50वें वर्ष के अवसर पर 9 अगस्त 2015 को राष्ट्र दिवस समारोह के लिए भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्री श्री अनंत गीते की सिंगापुर यात्रा; एक बौद्ध कला प्रदर्शनी के उद्घाटन के लिए 17 और 18 जून 2015 को पर्यटन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), संस्कृति राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और नागर विमानन राज्य मंत्री डा. महेश शर्मा की सिंगापुर यात्रा; तथा आंध्र प्रदेश के नए राजधानी शहर के सिलसिले में आंध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री श्री चन्द्रबाबू नायडू की सिंगापुर यात्रा।

सिंगापुर की ओर से भारत की की गई उच्च स्तरीय यात्राओं में निम्नलिखित शामिल हैं : सिंगापुर के गृह मंत्री एवं विधि मंत्री के शणमुगम ने 17 से 20 नवंबर 2015 के दौरान जयपुर में उत्थानशील राजस्थान साझेदारी शिखर बैठक के लिए एक कारोबारी शिष्टमंडल का नेतृत्व किया जिसमें सिंगापुर ने साझेदार देश के रूप में भाग लिया था; तीसरी भारत - अफ्रीका मंच शिखर बैठक (आई ए एफ एस) में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय में वरिष्ठ राज्य मंत्री, विदेश मंत्री तथा परिवहन मंत्री जोसेफिन टेव ने 28 से 30 अक्टूबर 2015 के दौरान नई दिल्ली का दौरा किया जहां सिंगापुर को एक विशेष आमंत्रिती के रूप में शामिल किया गया था, व्यापार एवं उद्योग मंत्री एस ईश्वरन ने सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली हुसैन लुंग की ओर से 22 अक्टूबर 2015 को आंध्र प्रदेश के नए राजधानी शहर अमरावती में

शिलान्यास समारोह में भाग लिया; जब एस ईश्वरन प्रधानमंत्री कार्यालय में मंत्री तथा व्यापार एवं उद्योग के लिए द्वितीय मंत्री थे तब उन्होंने आंध्र प्रदेश के नए राजधानी शहर अमरावती के सिलसिले में 20 जुलाई 2015 को और 25 मई 2015 को भारत का दौरा किया था, जिसके लिए सिंगापुर के एक परिसंघ द्वारा मास्टर प्लान तैयार किया गया; पूर्व विदेश मंत्री के शणमुगम ने जुलाई 2015 में तमिलनाडु, फरवरी 2015 में आंध्र प्रदेश और राजस्थान का दौरा किया; और वर्तमान विदेश मंत्री डा. विवियन बाला कृष्णन ने 12 अक्टूबर 2015 को दिल्ली में संयुक्त मंत्री स्तरीय समिति (जे एम सी) की चौथी बैठक में भाग लेने के लिए भारत का दौरा किया।

राजनीतिक

भारत - सिंगापुर संबंध साझे मूल्यों एवं दृष्टिकोणों, आर्थिक अवसरों तथा प्रमुख मुद्दों पर हितों में समानता पर आधारित हैं।

संबंध की रूपरेखा : भारत और सिंगापुर के बीच जिन करारों पर हस्ताक्षर किए गए हैं वे हमारे संबंध के बढ़ते विस्तार को दर्शात हैं तथा दोनों देशों की सरकारों, कारोबारी समुदाय के बीच गतिविधियों तथा जन दर जन संपर्कों की विशाल रूपरेखा प्रदान करते हैं। प्रमुख करारों में निम्नलिखित शामिल हैं: व्यापक आर्थिक सहयोग करार (2005), दोहरा कराधान परिहार करार (1994, प्रोटोकाल पर हस्ताक्षर 2011 में किए गए), द्विपक्षीय हवाई सेवा करार (1968, अप्रैल, 2013 में संशोधित), रक्षा सहयोग करार (2003, परिवर्धित करार पर नवंबर 2015 में हस्ताक्षर किए गए), विदेश कार्यालय परामर्श के लिए एम ओ यू (1994) और पारस्परिक कानूनी सहायता संधि (2005), और व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास के क्षेत्रों में सहयोग के लिए एम ओ यू। भारत और सिंगापुर के विदेश मंत्रियों की अध्यक्षता में एक संयुक्त मंत्री स्तरीय समिति (जे एम सी) है।

5-एस प्लैंक

भारत और सिंगापुर 5-एस प्लैंक पर राष्ट्रों का निर्माण कर रहे हैं जिन पर दोनों देशों द्वारा अगस्त 2014 में सहमति हुई थी जो इस प्रकार हैं :

(1) व्यापार एवं निवेश में वृद्धि : इस समय भारत सिंगापुर का 10वां सबसे बड़ा व्यापार साझेदार है, जबकि पिछले दो वर्षों में यह 12वें और 11वें स्थान पर था तथा 2015 में सिंगापुर के 631.5 बिलियन अमरीकी डालर के समग्र वैश्विक व्यापार में भारत का शेयर 2.55 प्रतिशत था। 2015 में सिंगापुर के साथ द्विपक्षीय व्यापार का मूल्य 16.08 बिलियन अमरीकी डालर था जो 2014 की तुलना में 8.11 प्रतिशत कम है। सिंगापुर को किए गए निर्यात का मूल्य 5.7 बिलियन अमरीकी डालर था जो वर्ष दर वर्ष आधार पर 24.4 प्रतिशत की गिरावट को दर्शाता है। सिंगापुर से किए गए आयात का मूल्य 10.4 बिलियन अमरीकी डालर था जो वर्ष दर वर्ष आधार पर 3.6 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है।

अप्रैल 2000 से दिसंबर 2015 के दौरान सिंगापुर से भारत में कुल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का मूल्य 43.2 बिलियन अमरीकी डालर था जो कुल एफ डी आई अंत:प्रवाह का 16 प्रतिशत है। जनवरी से दिसंबर 2015 की अवधि में सिंगापुर से विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (नवीनतम उपलब्ध आंकड़े) का मूल्य 10.98 बिलियन अमरीकी डालर था। जिन क्षेत्रों ने निवेशों को आकर्षित किया उनमें सूचना प्रौद्योगिकी, रीयल स्टेल, निर्माण, नवीकरणीय ऊर्जा एवं फार्मास्युटिकल शामिल हैं। भारत की ओर से सिंगापुर में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का मूल्य जनवरी से दिसंबर 2015 की अवधि में 5.27 बिलियन अमरीकी डालर था तथा जून 2015 तक कुल भारतीय निवेश का मूल्य 37.8 बिलियन अमरीकी डालर है।

(2) कनेक्टिविटी बढ़ाना : 1968 के हवाई सेवा करार को 2002 और 2005 में संशोधित किया गया। आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि के कारण द्विपक्षीय हवाई सेवा व्यवस्थाओं के लिए एम ओ यू पर अप्रैल 2013 में हस्ताक्षर किए गए। भारत और सिंगापुर के बीच 235 साप्ताहिक सेवाओं (470 साप्ताहिक उड़ानें) हैं जो भारत के 13 शहरों से सीधे जुड़ी हैं। सिंगापुर को 18 अतिरिक्त भारतीय प्वाइंट पर भी अक्सेस प्राप्त है जो आसियान देशों के लिए खुले हैं। सिंगापुर एयरलाइंस (एस आई ए) के विस्टारा, जो टाटा ग्रुप के साथ एक संयुक्त उद्यम है, में 49 प्रतिशत शेयर हैं। विस्टारा ने 9 जनवरी 2015 से भारत में घरेलू प्रचालन शुरू किया है।

(3) स्मार्ट शहर : सिंगापुर ने आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती का मास्टर प्लान विकसित किया है तथा और सहयोग के लिए राज्य सरकार के साथ बातचीत कर रहा है। मंत्री एस ईश्वरन ने 22 अक्टूबर 2015 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा अमरावती के शिलान्यास समारोह में सिंगापुर के प्रधानमंत्री का प्रतिनिधित्व किया था।

(4) कौशल विकास : ग्रीन फील्ड वर्ल्ड क्लास स्किल सेंटर (डब्ल्यूसीएससी) स्थापित करने में सहयोग के लिए आवश्यक रूपरेखा प्रदान करने के लिए 11 जुलाई 2012 को दिल्ली सरकार तथा सिंगापुर आई टी ई शिक्षा सेवा (आई टी ई ई एस) के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया था। यह 2013 में एक अस्थाय कैंपस से काम करने लगा है। सिंगापुर आई टी आई उदयपुर में पर्यटन प्रशिक्षण के लिए एक उत्कृष्टता केन्द्र विकसित करने में राजस्थान सरकार के साथ काम कर रहा है।

(5) राज्य फोकस : पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, राजस्थान और आंध्र प्रदेश के मुख्य मंत्रियों ने 2014 और 2015 में सिंगापुर का दौरा किया है। जनवरी 2016 में मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री ने 50वें ली कुआन यू एक्सचेंज फेलो के रूप में सिंगापुर का दौरा किया। सिंगापुर जनवरी 2015 में 7वीं वाइब्रेंट गुजरात शिखर बैठक में साझेदार देश था। सिंगापुर के गृह एवं विधि मंत्री के शणमुगम ने उत्थानशील राजस्थान साझेदारी शिखर बैठक (नवंबर 2015) में भाग लिया था जिसमें सिंगापुर साझेदार देश था। सिंगापुर सहयोग उद्यम (एस सी ई) तथा राजस्थान आवास बोर्ड जोधपुर एवं उदयपुर में दो टाउनशिप की संकल्पना के संयुक्त रूप से

विकास के लिए सहमत हुए हैं। सिंगापुर जल प्रबंधन एवं संरक्षण के क्षेत्र में भी राजस्थान सरकार के साथ काम कर रहा है। असम, सिक्किम, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और गुजरात के प्रतिनिधियों ने भी सिंगापुर का दौरा किया है।

रक्षा सहयोग

अक्टूबर 2003 में हस्ताक्षरित रक्षा सहयोग करार (डी सी ए) तथा नवंबर 2015 में हस्ताक्षरित परिवर्धित डी सी ए द्विपक्षीय रक्षा सहयोग के लिए एक प्रमुख रूपरेखा प्रदान करता है। करार की रूपरेखा के तहत रक्षा वार्ता में नीति वार्ता, कार्य समूह, स्टाफ वार्ता, अभ्यास, प्रशिक्षण की गतिविधियां, प्रदर्शनी एवं सम्मेलन शामिल हैं।

सांस्कृतिक गतिविधियां

संस्कृति में अंतर सरकारी सहयोग कला, पुरातत्व एवं विरासत के क्षेत्रों में सहयोग के लिए 1993 में हस्ताक्षरित एम ओ यू द्वारा अभिशासित है। सांस्कृतिक सहयोग पर कार्यपालक कार्यक्रम (ई पी) पर निर्दिष्ट अवधियों के लिए सहमति हुई है, 2015 से 2018 की नवीनतम अवधि के लिए कार्यपालक कार्यक्रम पर हस्ताक्षर नवंबर 2015 में प्रधानमंत्री मोदी की सिंगापुर यात्रा के दौरान किए गए थे। सिंगापुर राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के दक्षिण एशियाई अध्ययन कार्यक्रम में भारतीय अध्ययन पर एक अल्पावधिक चेयर स्थापित करने के लिए आई सी सी आर और सिंगापुर विश्वविद्यालय (एन यू एस) ने मार्च, 2010 में एक एम ओ यू पर हस्ताक्षर किया। सिंगापुर में विभिन्न सामुदायिक संगठनों द्वारा भारतीय सांस्कृतिक गतिविधियों का नियमित रूप से आयोजन किया जाता है। अनेक सांस्कृतिक सोसायटी जैसे कि टैंपल ऑफ फाइन आर्ट्स, सिंगापुर इंडियन फाइन आर्ट्स सोसायटी (एस आई एफ ए एस), अप्सरा आर्ट भारतीय शास्त्रीय नृत्य एवं कलाओं का प्रचार - प्रसार करते हैं। क्षेत्रीय एवं समुदाय आधारित संगठन भाषा शिक्षण, योग एवं संगीत का प्रचार प्रसार करने में सक्रिय हैं।

भारतीय समुदाय

जून 2015 में सिंगापुर की कुल आबादी 5.54 मिलियन थी जिसमें 3.9 मिलियन सिंगापुरियन और 1.6 मिलियन विदेशी शामिल हैं। भारतीयों का अनुपात लगभग 9.1 प्रतिशत या रेजीडेंट आबादी का लगभग 3.5 लाख है। इसके अलावा सिंगापुर में 1.6 मिलियन विदेशियों में अनुमानित तौर पर 3.5 लाख भारतीय प्रवासी हैं जो वित्तीय सेवाओं, आई टी में काम कर रहे हैं, छात्र हैं और मुख्य रूप से निर्माण एवं समुद्री क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। तमिल सिंगापुर की चार सरकारी भाषाओं में से एक है। स्कूलों में हिंदी, गुजराती, उर्दू, बंग्ला, एवं पंजीबी भी पढ़ाई जाती है। भारतीय समुदाय का लगभग दो तिहाई हिस्सा तमिलों का है। पंजीबी, मलयालमी एवं सिंधी अन्य प्रमुख समुदाय हैं।

कोंसुलर मामले

भारतीय मजदूरों सहित भारतीय नागरिकों के कल्याण एवं सेहत से संबंधित मुद्दे कोंसुलर जिम्मेदारियों में प्रमुखता से शामिल हैं। अनुमान है कि लगभग 1.5 लाख भारतीय सिंगापुर में, मुख्य रूप से निर्माण एवं समुद्री क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। सिंगापुर "उत्प्रवासन क्लियरेंस अपेक्षित" की श्रेणी में नहीं आता है।

उपयोगी संसाधन :

भारतीय उच्चायोग, सिंगापुर की वेबसाइट :
https://www.hcisingapore.gov.in/
भारतीय उच्चायोग, सिंगापुर का फेसबुक पेज :
https://www.facebook.com/IndiaInSingapore

***

फरवरी, 2016